राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी

सादर प्रकाशनार्थ :-

जयपुर, 08 जून। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने आज प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण मँहगाई बेलगाम हो गई है तथा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है जिसके खिलाफ दिनांक 11 जून, 2021 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना गाईडलाइन्स की पालना करते हुए पेट्रोल पम्पों के सामने विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे। इन विरोध प्रदर्शनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, विधायकगण, सांसदगण, विधायक प्रत्याशीगण, सांसद प्रत्याशीगण, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यगण, सभी जप्रतिनिधिगण, प्रमुख कांग्रेसजन, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के निवर्तमान पदाधिकारीगण भाग लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि अप्रेल, 2014 में जब देश में डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार का शासन था उस वक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 108 डॉलर प्रति बैरल थे तथा देश में पेट्रोल के दाम 71 रूपये प्रति लीटर व डीजल के दाम 57 रूपये प्रति लीटर थे, किन्तु आज जून माह में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 61 डॉलर प्रति बैरल होने के बावजूद भी पेट्रोल के दाम 102.82 रूपये प्रति लीटर है तथा डीजल के दाम 95.96 रूपये प्रति लीटर हो गये हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय डीजल पर वेट 3.56 रूपये था जो अब 32 रूपये हो गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के 7 वर्ष के शासन के दौरान पेट्रोल व डीजल पर 12 बार एक्साईज ड्यूटी बढ़ाई गई और केवल दो बार घटाई गई है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर, 2017 में दो रूपये तथा वर्ष 2018 में दो रूपये एक्साईज ड्यूटी घटाई गई थी जबकि सरकार ने हमेशा पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी ही की है। उन्होंने कहा कि मई 2020 में पेट्रोल पर 10 रूपये तथा डीजल पर 13 रूपये एकमुश्त एक्साईज ड्यूटी की बढ़ोत्तरी की गई जिससे केन्द्र को प्राप्त होने वाली एक्साईज ड्यूटी 32.92 रूपये पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र को मिलने वाली स्पेशल एक्साईज, एडिशनल एक्साईज एवं सेस के कारण पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल पर लगने वाली उस एक्साईज ड्यूटी को घटाया गया है जिसमें से राज्यों को हिस्सा मिलता है, लेकिन केन्द्र को मिलने वाली एक्साईज ड्यूटी को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल व डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 200 प्रतिशत तथा डीजल पर 336 प्रतिशत एक्साईज ड्यूटी बढ़ा दी है, वहीं सब्सिडी से मिलने वाले सिलेण्डर की कीमतों में 200 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है जिसके कारण सिलेण्डर की कीमत आज 800 पर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने स्वीकार किया है कि पेट्रोल व डीजल के टैक्स कलेक्शन में 459 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। उन्होंने कहा कि जो घरेलू गैस सिलेण्डर 410 रूपये का 1 मार्च, 2014 को मिलता था, आज 800 रूपये से अधिक उसके लिये आम जनता को चुकाना पड़ रहा है।

श्री डोटासरा ने कहा कि आज देश में प्रत्येक वस्तु मंहगी होकर आम आदम की पहुंच से दूर हो रही है। उन्होंने कहा कि लोहे की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है, साथ ही 2 माह में शक्कर 36 रूपये से 40 रूपये प्रति किलो, चाय पत्ती 240 रूपये से 300 रूपये प्रति किलो, चावल 30 रूपये प्रति किलो वाला 40 रूपये हो गया। इसी प्रकार गुड 40 से 50, चना दाल 60 से 75, अरहर दाल 100 से 125, उड़द दाल 95 से 110, मिर्ची 170 से 200, काबुली चना 100 से 125 हो गया है। साबूदाना, नमकीन, फल एवं सब्जियों के दामों में भी जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही सरसों का तेल 130 से 200, रिफाइंड तेल 105 से 170, सूरजमुखी का तेल 130 से 180 हो गया है। जनवरी माह में आटा 25 रूपये किलो मिल रहा था जो अब 32 रूपये प्रति किलो हो गया है। उन्होंने कहा कि सब्जी, फल, खाद्य सामग्री, खाद्य तेलों कीह बढ़ी हुई कीमतों के कारण आम आदमी के जीवनयापन पर संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए बढ़ती हुई मंहगाई के विरूद्ध पूरे देश में कोरोना गाईडलाइन्स की पालना करते हुए पेट्रोल पम्पों के सामने केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवर्तमान जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षगण वर्चुअल अथवा अन्य तरीके से कार्यकर्ताओं से सम्पर्क कर प्रदर्शन की रूपरेखा एवं स्थान तय करेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के दिए सुझावों पर ध्यान नहीं देते हैं तथा पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी जी के पत्रों का जवाब भी नहीं देते हैं, ऐसी परस्थिति में लोकतंत्र में प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि देश के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खतरे से बचाव हेतु सभी देशवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की थी, किन्तु केन्द्र सरकार देश के लिए वैक्सीन नीति बनाने में असफल रही। प्रधानमंत्री जी देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की भयावहता को या तो समझ नहीं सके या उन्होंने जानबूझकर इस

खतरे को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की प्रथम लहर के समय प्रधानमंत्री जी ने समस्त देशवासियों को आश्वस्त किया था कि देश में वैक्सीन बन रही है तथा सभी को केन्द्र सरकार द्वारा वैक्सीन उपलब्ध करवाई जायेगी, उन्होंने बजट में भी वैक्सीनेशन हेतु 35000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया, लेकिन महामारी की दूसरी लहर आने पर मोदी सरकार देशवासियों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने और उनकी जान बचाने में असफल रही। उन्होंने कहा कि हमारी ही देश में बनी वैक्सीन विदेशों में जाती रही और प्रधानमंत्री जी खुद की पीठ थपथपाते रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी स्वयं बंगाल आदि प्रदेशों के चुनावों में व्यस्त रहे और देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने खतरनाक तरीके से पैर पसार लिये, जिस कारण देश में लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे विकट समय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने से हाथ खड़े कर दिये और वैक्सीन आपूर्ति सहित आर्थिक संसाधन जुटाने के समस्त दायित्व राज्यों पर डाल दिये। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस नेता श्री राहुल गाँधी जी ने एवं देश के अनेक मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से निवेदन किया कि देश के लोगों को कोरोना महामारी से बचाने हेतु वैक्सीनशन ही एकमात्र उपाय है जिस हेतु केन्द्र सरकार को अपने दायित्वों की पालना में देश के समस्त नागारिकों को कोरोना महामारी का टीका मुफ्त लगवाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से यह भी पेशकश की कि कोरोना महामारी के टीके की आपूर्ति केन्द्र करे भले ही कीमत राज्यों से वसूल ली जाए किन्तु केन्द्र सरकार राज्यों को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध करवाने में विफल रही जिस कारण देश के लाखों लोगों की जान गई एवं असंख्य परिवार उजड़ गये। उन्होंने कहा कि जब पूरे विश्व में मोदी सरकार की वैक्सीन नीति के विफल होने की चर्चा हुई तथा केन्द्र सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय जगत में निन्दा होने लगी तो केन्द्र सरकार ने मजबूरी में अपनी घटती लोकप्रियता एवं धूमिल होती छवि के परिणामस्वरूप मजबूरी में देश के सभी 18 वर्ष से बड़ी उम्र के लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने का निर्णय लेकर अपने पुराने निर्णय को बदला। जिस वक्त देश के असंख्य लोगों के जीवन की रक्षा करने का समय था उस वक्त वैक्सीनेशन करने के दायित्व को नजरअंदाज करना प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री जी कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पीड़ितों को जीवन रक्षक दवाएं, ऑक्सीजन तथा वैक्सीन उपलब्ध करवाने में विफल रहे जिस कारण से आज उनकी लोकप्रियता में भारी कमी आई है, इसी मजबूरी के चलते प्रधानमंत्री जी ने अपना निर्णय बदला तथा देश में 18 वर्ष से बड़ी आयु वालों के लिये मुफ्त टीका लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि यदि सभी को मुफ्त टीका लगवाया जायेगा तो प्राईवेट अस्पतालों में टीका लगाने हेतु वैक्सीन की कीमत

वसूलने की छूट क्यों प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने राज्य की जनता को टीका लगाने हेतु बेहतरीन प्रबंधन किया एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप किया, टीकाकरण अभियान में राजस्थान अग्रणी राज्य बना, किन्तु तत्पश्चात् राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की आपूर्ति बाधित हो गई जिस कारण राज्य की जनता को कष्ट सहने पड़े। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराने की बजाए राज्य सरकार के विरूद्ध झूठे एवं मनगढ़त आरोप के आधार पर दुष्प्रचार प्रारम्भ कर दिया। देश में वैक्सीन की वेस्टेज का प्रतिशत 6 है किन्तु राजस्थान सरकार के द्वारा किये गये प्रबंधन के कारण राज्य में केवल 2 प्रतिशत वैक्सीन की डोज वेस्ट हुई।

श्री डोटासरा ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगाने हेतु नीति बनाई जाए जिससे बच्चों का जीवन सुरक्षित हो सके तथा स्कूली बच्चे अपने स्कूल एवं शिक्षण संस्थाओं में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।